

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal**(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)****(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)***** Vol-2* *Issue-8* *August 2025*****डिजिटल बाजार में गिग इकोनमी का प्रभाव: भारतीय
अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में****डॉ० विजया कुमारी***सहायक प्राचार्य (एकेडमिक लेवल-11), अर्थशास्त्र विभाग, पी. सी. विज्ञान कालेज, छपरा, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा***सारांश**

इस शोध पत्र में भारत में गिग अर्थव्यवस्था के विकसित परिदृश्य की जांच की गई है, इसकी वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और देश के श्रम बाजार और समग्र अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। जनसांख्यिकीय रुझानों, तकनीकी प्रगति और नीतिगत ढांचे की खोज करके, हमारा उद्देश्य भारत में गिग श्रमिकों, व्यवसायों और नीति निर्माताओं के लिए आगे आने वाले अवसरों और चुनौतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। आंकड़ों, प्रवृत्तियों और विशेषज्ञ विश्लेषणों की गहन परीक्षा के माध्यम से, यह शोध पत्र तर्क देता है कि चूंकि भारत में गिग इकोनमी तेजी से विस्तार कर रही है और कई अवसर प्रदान कर रही है, साथ ही महत्वपूर्ण चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है कि यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सकारात्मक योगदान देता है। भारतीय संदर्भ में, गिग इकोनमी ने अद्वितीय विशेषताओं को प्राप्त किया है, जिसे देश के विशाल और विविध श्रम बाजार, तेजी से बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे और विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों द्वारा आकार दिया गया है। एक बड़े युवा जनसांख्यिकीय के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत गिग अर्थव्यवस्था मॉडल के लिए अपार क्षमता और महत्वपूर्ण चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। इस शोधपत्र का उद्देश्य भारत में गिग अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करना है। यह इस क्षेत्र के आकार और दायरे का पता लगाएगा, इसके विकास को चलाने वाले कारकों की जांच करेगा और श्रमिकों, व्यापक अर्थव्यवस्था और पारंपरिक उद्योगों पर इसके प्रभाव का आकलन करेगा। इसके अलावा, इस अध्ययन में नियामक परिदृश्य पर भी ध्यान दिया जायेगा जो लचीलेपन के साथ कार्यकर्ता सुरक्षा को संतुलित करने के जटिल कार्य को संबोधित करेगा, जो गिग कार्य की विशेषता है।

परिचय

अल्पकालिक अनुबंधों, फ्रीलांस काम और अस्थायी पदों की विशेषता वाली गिग अर्थव्यवस्था, दुनिया भर में श्रम बाजारों में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और बदलती आर्थिक स्थितियों द्वारा सुगम काम का यह नया प्रतिमान, पारंपरिक रोजगार संरचनाओं को नया आकार दे रहा है और श्रमिकों और व्यवसायों दोनों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है। हाल के वर्षों में, भारत ने गिग वर्क में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जिससे यह अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। गिग इकोनमी में राइड-हेलिंग और फूड डिलीवरी सेवाओं से लेकर आईटी, डिजाइन और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में पेशेवर फ्रीलांसिंग तक कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर, इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसमें उबर, एयरबीएनबी और फिवर जैसे प्रमुख खिलाड़ी घरेलू नाम बन गए हैं। इस प्रवृत्ति को तकनीकी प्रगति, मिलेनियल्स और जेन जेड के बीच काम की प्राथमिकताओं में बदलाव और व्यवसायों को अपने कार्यबल में लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता से बढ़ावा मिला है। जैसा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपना प्रक्षेपवक्र जारी रखता है, गिग अर्थव्यवस्था की भूमिका और निहितार्थ को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह शोधपत्र भारत में काम के भविष्य, बेरोजगारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए गिग अर्थव्यवस्था की क्षमता और इस क्षेत्र में सतत और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत ढांचे के बारे में चल रही बातचीत में योगदान करना चाहता है।

विश्व स्तर पर गिग अर्थव्यवस्था का विकास

गिग वर्क की अवधारणा पूरी तरह से नई नहीं है, अस्थायी और अनुबंध आधारित रोजगार सदियों से मौजूद है। हालाँकि, आधुनिक गिग अर्थव्यवस्था जैसा कि हम आज जानते हैं, इसकी जड़ें 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत की डिजिटल क्रांति में हैं। इंटरनेट के आगमन, स्मार्टफोन और हाई-स्पीड मोबाइल नेटवर्क के प्रसार के बाद, गिग अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ।

वैश्विक गिग अर्थव्यवस्था में प्रमुख मील के पत्थर में 1995 में क्रेगलिस्ट का शुभारंभ शामिल है, जिसने स्थानीय गिग काम की सुविधा प्रदान की, 1999 में एलेंस (अब अपवर्क) की स्थापना, जिसने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का बीड़ा उठाया और उबर (2009) और लिफ्ट (2012) जैसे राइड-हेलिंग दिग्गजों की स्थापना ने इसे बढ़ाया है। इन प्लेटफार्मों ने नाटकीय रूप से काम के परिदृश्य को बदल दिया और रोजगार के नए मॉडल पेश किए जो सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच लचीलेपन और सीधे कनेक्शन को प्राथमिकता देते थे।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

भारत में गिग इकॉनमी के उदय को समझने के लिए, देश के व्यापक आर्थिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। भारत के श्रम बाजार की विशेषता इसके विशाल आकार की है, जिसमें 500 मिलियन से अधिक लोगों का कार्यबल है, और इसकी जटिलता, जिसमें एक बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र और एक बढ़ती औपचारिक अर्थव्यवस्था दोनों शामिल हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। चूंकि इन सुधारों ने आर्थिक विकास को गति दी और नए अवसर पैदा किए, विशेष रूप से आईटी और बीपीओ जैसे सेवा क्षेत्रों में, इनसे रोजगार पैटर्न में भी बदलाव आया। हमारे औपचारिक नौकरी क्षेत्र हर साल बढ़ते हुए बाजार में प्रवेश के इच्छुक नौकरी चाहने वालों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल नहीं रख पाया है। औपचारिक नौकरी क्षेत्र में चुनौतियों, जिनमें कौशल बेमेल, कठोर श्रम कानून और विनिर्माण विकास की धीमी गति शामिल हैं, ने विशेष रूप से युवाओं के बीच बेरोजगारी और बेरोजगारी के उच्च स्तर में योगदान दिया है। इस परिदृश्य ने गिग वर्क सहित रोजगार के वैकल्पिक रूपों के लिए एक पृष्ठभूमि बनाई है।

साहित्य समीक्षा—

गिग अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर अकादमिक और नीतिगत रुचि का विषय रही है, जिसमें साहित्य का एक बढ़ता स्तर इसके विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है। यह समीक्षा भारतीय संदर्भ से प्रासंगिक अध्ययनों पर ध्यान देने के साथ मौजूदा शोध से प्रमुख निष्कर्षों को संश्लेषित करती है।

गिग अर्थव्यवस्था पर वैश्विक दृष्टिकोण: गिग इकॉनमी को परिभाषित करना

गिग अर्थव्यवस्था पर वैश्विक साहित्य भारत में इसके विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। 'गिग इकॉनमी' शब्द अकादमिक साहित्य में विभिन्न व्याख्याओं के अधीन रहा है। फ्राइडमैन (2014) ने इसे अल्पकालिक अनुबंधों, फ्रीलांस काम और अस्थायी पदों की विशेषता वाले श्रम बाजार के रूप में वर्णित किया है। यह अर्थव्यवस्था के उदय का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, इसकी जड़ों को तकनीकी प्रगति और बदलती कार्य प्राथमिकताओं का पता लगाता है। डी स्टेफानो (2015) गंभीर रूप से गिग श्रमिकों के वर्गीकरण की जांच करता है, उनकी अस्पष्ट स्थिति से उत्पन्न कानूनी और सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। वलास और शोर (2020) इन कार्य व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका पर जोर देते हैं। कई अध्ययनों ने वैश्विक स्तर पर गिग अर्थव्यवस्था के विकास की जांच की है। कैसी और लेडोनवित्रा (2018) देशों में दूरस्थ गिग कार्य के विस्तार को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन श्रम प्लेटफार्मों से डेटा का उपयोग करते हैं। उनके निष्कर्ष गिग वर्क में लगातार वृद्धि का संकेत देते हैं, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट (2016) का अनुमान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कामकाजी उम्र की आबादी का 20–30% स्वतंत्र कार्य के किसी न किसी रूप में संलग्न है।

भारतीय गिग अर्थव्यवस्था पर अध्ययन

भारतीय गिग अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट अनुसंधान बढ़ रहा है, हालांकि यह पश्चिमी संदर्भों में अध्ययन की तुलना में सीमित है। कासलीवाल (2020) भारत में गिग अर्थव्यवस्था के पहले व्यापक अवलोकन में से एक प्रदान करता है, इसके आकार का अनुमान लगाता है और रोजगार सृजन के लिए इसकी क्षमता की खोज करता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन (2021) की रिपोर्ट इस क्षेत्र के विकास और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसके संभावित योगदान पर अनुमान प्रस्तुत करती है। हाल के वर्षों में भारत में गिग इकॉनमी पर शोध काफी बढ़ गया है। रामचंद्रन और रमन (2022) भारतीय गिग अर्थव्यवस्था की संरचना और विकास चालकों का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं। वे इसके विस्तार को बढ़ावा देने में जनसांख्यिकीय कारकों, तकनीकी प्रगति और आर्थिक आवश्यकताओं की भूमिका को उजागर करते हैं। भारत की गिग अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग (2022) की रिपोर्ट इसकी वर्तमान स्थिति और

भविष्य की क्षमता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में गिग वर्कफोर्स 2029–30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन हो सकता है, जिससे यह देश के श्रम बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाएगा।

गिग वर्कर्स के अनुभवों और चुनौतियों पर शोध

कई अध्ययनों ने भारत में गिग वर्कर्स के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया है। सूरी (2018) नई दिल्ली में राइड-हेलिंग ड्राइवरों की कामकाजी परिस्थितियों की जांच करता है, एल्गोरिथम नियंत्रण और अनिश्चित रोजगार के मुद्दों पर प्रकाश डालता है। कश्यप और भाटिया (2018) भारत में विभिन्न प्लेटफार्मों पर गिग श्रमिकों काम के लचीलेपन और आय सुरक्षा के बीच व्यापार-बंद को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा सामना की जाने वाली प्रेरणाओं और चुनौतियों का पता लगाते हैं। गिग अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव साहित्य में व्यापक बहस का विषय रहे हैं। वुड एट अल (2019) भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिग श्रमिकों के लिए कार्य जीवन की गुणवत्ता की जांच करते हैं। वे पाते हैं कि चूंकि गिग वर्क लचीलापन प्रदान करता है, परंतु यह अक्सर आय असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कमी के साथ आता है।

गिग अर्थव्यवस्था का आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन—

भारत में गिग अर्थव्यवस्था के आर्थिक निहितार्थों का पता अकादमिक शोधकर्ताओं और उद्योग रिपोर्टों दोनों द्वारा लगाया गया है। कोरेक (2018) भारत की रोजगार चुनौतियों का समाधान करने के लिए गिग अर्थव्यवस्था की क्षमता का विश्लेषण करता है, जबकि नौकरी की गुणवत्ता और श्रमिक सुरक्षा के बारे में चिंताओं को भी ध्यान में रखता है। एसोचौम (2020) रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था में गिग वर्क के क्षेत्रवार योगदान में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

नीति और नियामक अनुसंधान—

गिग अर्थव्यवस्था की विकसित प्रकृति को देखते हुए, नीति और नियामक पहलुओं पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। अग्रवाल एवं अन्य (2020) भारत में गिग वर्क के लिए मौजूदा श्रम कानूनों की प्रयोज्यता की जांच करना, प्रमुख अंतरालों की पहचान करना और संभावित नीति समाधानों का प्रस्ताव करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट (2021) देशों में गिग इकॉनमी नियमों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करती है, जो भारतीय संदर्भ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गिग अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न नियामक चुनौतियों ने महत्वपूर्ण विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। हीक्स एवं अन्य (2021) भारत सहित विभिन्न देशों में डिजिटल श्रम प्लेटफार्मों के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। वे एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए तर्क देते हैं जो कार्यकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देता है। भारतीय संदर्भ में, अग्रवाल एवं अन्य (2023) गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के निहितार्थों की जांच करते हैं। उनके विश्लेषण से गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान नीतिगत प्रयासों की क्षमता और सीमाओं दोनों का पता चलता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में गिग अर्थव्यवस्था की स्थिति का व्यापक, अप-टू-डेट विश्लेषण प्रदान करके, हाल के डेटा और शोध निष्कर्षों को संश्लेषित करके और श्रमिकों, अर्थव्यवस्था और नियामक परिदृश्य पर इसके बहुमुखी प्रभावों में अंतर्दृष्टि प्रदान करके इनमें से कुछ अंतरालों को संबोधित करना है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य है—

1. भारत में गिग अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. इसके विकास के लिए प्रमुख चालकों और बाधाओं की पहचान करना।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव की जांच करना।
4. नीतिगत निहितार्थों और संभावित नियामक ढांचे का पता लगाना।
5. भारत में गिग अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य के रुझान और परिदृश्य प्रोजेक्ट करना।

इन उद्देश्यों को संबोधित करके, हम गिग अर्थव्यवस्था पर साहित्य में वृद्धि योगदान करना चाहते हैं और इस तेजी से विकसित परिदृश्य को नेविगेट करने वाले नीति निर्माताओं, व्यवसायों और श्रमिकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

शोधपद्धति

भारत में गिग अर्थव्यवस्था के भविष्य का व्यापक विश्लेषण करने के लिए, यह अध्ययन मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान तकनीकों के संयोजन के साथ एक मिश्रित-तरीकों के दृष्टिकोण को नियोजित करता है। हमारी कार्यप्रणाली में निम्नलिखित घटक शामिल हैं।

साहित्य समीक्षा

हमने वैश्विक स्तर पर और विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित अकादमिक साहित्य, उद्योग

रिपोर्टों और सरकारी प्रकाशनों की व्यापक समीक्षा की। इस समीक्षा ने हमारे अध्ययन के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा स्थापित करने और क्षेत्र में प्रमुख रुझानों, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद की।

माध्यमिक डेटा विश्लेषण— हमने विभिन्न स्रोतों से द्वितीयक डेटा का विश्लेषण किया, जिनमें शामिल हैं सरकारी आँकड़े (जैसे, श्रम बल सर्वेक्षण, आर्थिक संकेतक), अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) से रिपोर्ट, भारत में संचालित गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म का डेटा उद्योग रिपोर्ट और बाजार अनुसंधान अध्ययन इत्यादि। इस मात्रात्मक विश्लेषण ने भारत में गिग अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान की और भविष्य के अनुमानों के रुझानों की पहचान करने में मदद की।

भारत में गिग अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति

• गिग सेक्टर का आकार और विकास

भारत में गिग अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में तेजी से विकास का अनुभव किया है, जो देश के श्रम बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। जबकि बहुत अधिक गिग वर्क की अनौपचारिक प्रकृति के कारण सटीक आंकड़े निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है, कई अध्ययन इस क्षेत्र के आकार और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं—

- 1. गिग वर्कर्स की अनुमानित संख्या:** बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का गिग वर्कफोर्स 15 मिलियन श्रमिकों का अनुमान है। आने वाले वर्षों में यह संख्या काफी बढ़ने की उम्मीद है। यह संख्या 2025 तक 25–30 मिलियन पहुंचने की उम्मीद है। (स्रोत: पीडब्ल्यूसी इंडिया रिपोर्ट, 2022)
- 2. बाजार का आकार और अनुमान:** एक ही रिपोर्ट में कहा गया है कि गिग इकोनॉमी में अकेले भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में 90 मिलियन नौकरियों की सेवा करने की क्षमता है, जिसमें लंबी अवधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.25% तक जोड़ने की क्षमता है। गिग अर्थव्यवस्था का भारतीय जीडीपी में योगदान 2022 में लगभग 1.5% था, इसे 2025 में 2% होने का अनुमान है। (स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, 2022)
- 3. विकास दर:** भारत में गिग इकोनॉमी 17% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रही है, जो पारंपरिक रोजगार क्षेत्रों में वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा रही है। ASSOCHAM की एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि भारत की गिग इकोनॉमी 2024 तक 17% की CAGR से बढ़कर +455 बिलियन हो जाएगी।

प्रमुख उद्योग और प्लेटफॉर्म

भारत में गिग इकोनॉमी विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसमें कुछ उद्योग विशेष रूप से गिग वर्क मॉडल को अपनाने के लिए मजबूत हैं—

- 1. राइड-हेलिंग और डिलीवरी सेवाएं** ओला, उबर, स्विगी और ज़ोमैटो जैसी कंपनियां भारत में गिग वर्क में सबसे आगे रही हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों ड्राइवर और डिलीवरी पार्टनर कार्यरत हैं। भारत में उबर और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता के आधार में सालाना औसतन 20% की वृद्धि हो रही है। (स्रोत: उबर और स्विगी की वार्षिक रिपोर्ट, 2023)
- 2. व्यावसायिक सेवाएं** न्यूवता, Freelancer.com और फ्लेक्सिंग इट जैसे भारतीय स्टार्टअप जैसे प्लेटफॉर्म आईटी, डिजाइन, सामग्री निर्माण और परामर्श जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों को पूरा करते हैं।
- 3. होम सर्विसेज और टास्क-बेस्ड प्लेटफॉर्म** रू अर्बन कंपनी (पूर्व में अर्बनक्लैप) जैसी कंपनियों ने ऑन-डिमांड होम सेवाओं को लोकप्रिय बनाया है, जबकि टास्करैबिट (जिसने 2019 में भारत में प्रवेश किया था) टास्क-आधारित गिग वर्क की सुविधा प्रदान करता है।
- 4. प्रमुख व्यवसायी** वैश्विक खिलाड़ियों के अलावा, भारतीय स्टार्टअप ने गिग इकोनॉमी में महत्वपूर्ण पैठ बनाई है। उल्लेखनीय भारतीय प्लेटफॉर्मों में डंजो (हाइपरलोकल डिलीवरी), हाउसजॉय (होम सर्विसेज), और अविग्न (विभिन्न क्षेत्रों में गिग वर्क) शामिल हैं।

गिग वर्कर्स की जनसांख्यिकी

भारत में गिग वर्कर्स की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल काम के इस नए रूप के अवसरों और चुनौतियों दोनों को दर्शाती है—

- 1. आयु वितरण—** भारत में अधिकांश गिग वर्कर्स युवा हैं। PayPal के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में 41% फ्रीलांसर 30 वर्ष से कम आयु के हैं, अन्य 33% 31–40 वर्ष के बीच हैं।
- 2. लिंग प्रतिनिधित्व—** जबकि सटीक आंकड़े क्षेत्र के अनुसार भिन्न होते हैं, कुल मिलाकर, भारत में गिग अर्थव्यवस्था पुरुष—प्रधान है। हालांकि, सामग्री निर्माण और पेशेवर सेवाओं जैसे कुछ क्षेत्रों में उच्च महिला भागीदारी देखी जाती है। गिग इकॉनमी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल चल रही है।
- 3. शैक्षिक पृष्ठभूमि—** गिग श्रमिकों की शैक्षिक प्रोफाइल क्षेत्र के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है। जबकि राइड—हेलिंग और डिलीवरी सेवाएं अक्सर कम औपचारिक शिक्षा स्तर वाले श्रमिकों को नियुक्त करती हैं, पेशेवर सेवाओं के गिग श्रमिकों में आमतौर पर उच्च शिक्षा योग्यता होती है।
- 4. भौगोलिक वितरण—** गिग वर्क मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, विशेष रूप से बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में। हालांकि, इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के साथ, गिग अवसर धीरे-धीरे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं।

भारत में गिग इकॉनमी की वर्तमान स्थिति तेजी से संक्रमण में एक क्षेत्र को दर्शाती है, जो महत्वपूर्ण विकास और उभरती गतिशीलता द्वारा चिह्नित है।

भारत में गिग वर्क के उदय और विकास में योगदान देने वाले कारक

भारत में गिग अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार को कारकों के संगम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें तकनीकी प्रगति से लेकर सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना शामिल है। भारत में गिग अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास को चलाने के लिए कई कारक अभिसरण हुए हैं।

तकनीकी प्रगति

प्रौद्योगिकी गिग अर्थव्यवस्था का एक मौलिक प्रवर्तक रहा है, जो काम के लिए नए रास्ते बना रहा है और सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच कनेक्शन को सुविधाजनक बना रहा है।

1. व्यापक रूप से स्मार्टफोन अपनाना— भारत ने 2021 तक 500 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ स्मार्टफोन के उपयोग में विस्फोटक वृद्धि देखी है। इस व्यापक गोद लेने ने लाखों संभावित श्रमिकों के हाथों में गिग अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए उपकरण डाल दिए हैं।

2. इंटरनेट की पैठ बढ़ाना— भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2021 में 750 मिलियन को पार कर गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से तेजी से विकास देखा गया। डिजिटल कनेक्टिविटी के इस विस्तार ने शहरी केंद्रों से परे गिग प्लेटफार्मों की पहुंच बढ़ा दी है।

3. उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफार्मों और ऐप्स का विकास— सहज, उपयोग में आसान ऐप्स के प्रसार ने गिग श्रमिकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए प्रवेश की बाधा को कम कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म मांग के साथ आपूर्ति का कुशलतापूर्वक मिलान करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, जिससे गिग वर्क की व्यवहार्यता बढ़ जाती है।

4. शहरीकरण और बदलती कार्य प्राथमिकताएं— भारत में तेजी से शहरीकरण ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच जीवन शैली और काम की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। कार्य-जीवन संतुलन, और कई हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता की बढ़ती इच्छा है— ऐसी ज़रूरतें जो अक्सर गिग कार्य व्यवस्था द्वारा अच्छी तरह से परोसी जाती हैं।

कार्य वरीयताओं को बदलना

काम के प्रति दृष्टिकोण को बदलना, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के बीच, ने गिग इकॉनमी मॉडल के लिए एक ग्रहणशील वातावरण बनाया है।

1. पारंपरिक रोजगार के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव: 'जीवन के लिए नौकरी' की धारणा के साथ मोहभंग बढ़ रहा है। कई कार्यकर्ता अब अपने करियर को एक संगठन के भीतर रैखिक प्रगति के बजाय अनुभवों के पोर्टफोलियो के रूप में देखते हैं।

आर्थिक कारक

भारत में आर्थिक वास्तविकताओं ने गिग वर्क को कई व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक या आवश्यक विकल्प बना दिया है।

1. उच्च बेरोजगारी दर, विशेष रूप से युवाओं में— दिसंबर 2021 (सीएमआईई डेटा) में भारत की बेरोजगारी दर 7.

91% तक पहुंचने और युवा बेरोजगारी काफी अधिक होने के साथ, कई लोग पारंपरिक रोजगार के विकल्प के रूप में गिग वर्क की ओर रुख कर रहे हैं।

2. पूरक आय की आवश्यकता जीवन यापन की बढ़ती लागत, कई क्षेत्रों में स्थिर मजदूरी के साथ, व्यक्तियों को गिग वर्क के माध्यम से अतिरिक्त आय स्रोतों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है।

3. आउटसोर्सिंग और फ्लेक्सिबल स्टाफिंग के प्रति कॉर्पोरेट रुझान— कंपनियां लागत कम करने और चपलता बढ़ाने के लिए लचीले स्टाफिंग मॉडल को तेजी से अपना रही हैं, जिससे गिग वर्कर्स के लिए अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं।

सरकार की पहल

कई सरकारी कार्यक्रमों ने अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता को बढ़ाकर गिग अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन किया है।

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम— इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म का समर्थन करना जो गिग वर्क की सुविधा प्रदान करता है।
2. कौशल भारत मिशन— कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके, इस कार्यक्रम ने एक अधिक सक्षम कार्यबल बनाने में मदद की है, जिनमें से कुछ गिग अर्थव्यवस्था में अवसर पाते हैं।
3. स्टार्ट-अप इंडिया योजना— इस पहल ने उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जिससे कई भारतीय गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ है।

इन तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत कारकों की परस्पर क्रिया ने भारत में गिग अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की है। गिग वर्कर्स के 60% ने अपने कार्य क्षमता में सुधार के लिए तकनीकी एवं पेशेवर क्षमताओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। (स्रोत: जॉब्स इंडिया सर्वे, 2023)

गिग वर्क के बहुमुखी प्रभाव—

श्रमिकों पर प्रभाव— गिग इकोनॉमी ने भारत में काम के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जिससे श्रमिकों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों आ गई हैं। इस नए आर्थिक मॉडल में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर गिग वर्क के बहुमुखी प्रभाव की जांच करता है।

लचीलापन और स्वायत्तता

गिगकार्य के सबसे अधिक में से एकतरित लाभ यह लचीलापन प्रदान करता है—

1. काम के घंटे और स्थान पर नियंत्रण— गिग श्रमिकों को अक्सर यह चुनने की स्वतंत्रता होती है कि वे कब और कहाँ काम करते हैं। यह लचीलापन अन्य जिम्मेदारियों या वरीयताओं के साथ काम को संतुलित करने वालों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। 2023 के एक सर्वेक्षण के अनुसार गिग वर्कर्स के 70 प्रतिशत ने लचीलापन एवं स्वायत्त को अपने काम की सबसे बड़ी सकारात्मक विशेषता बतायी है। (स्रोत: कोऑपरेटिव इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया रिपोर्ट, 2023)
2. परियोजनाओं और ग्राहकों को चुनने की क्षमता— कई गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों को उन परियोजनाओं का चयन करने की अनुमति देते हैं जो उनके कौशल और रुचियों के साथ संरेखित होते हैं, जो पारंपरिक रोजगार में हमेशा उपलब्ध नहीं होने वाली स्वायत्तता की डिग्री प्रदान करते हैं।
3. कार्य-जीवन संतुलन विचार— जबकि गिग वर्क कुछ के लिए बेहतर कार्य-जीवन संतुलन प्रदान कर सकता है, दूसरों को काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच धुंधली रेखाएं प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण लगती हैं।

आय क्षमता और स्थिरता

गिग वर्क के वित्तीय पहलू एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं—

1. कमाई के अवसर और आय का स्तर— कुछ कुशल गिग श्रमिक, विशेष रूप से तकनीक और पेशेवर सेवाओं में, पारंपरिक नौकरियों की तुलना में अधिक कमाई की रिपोर्ट करते हैं। ASSOCHAM की 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि कुशल गिग वर्कर्स पारंपरिक भूमिकाओं में अपने समकक्षों की तुलना में 2-3 गुना अधिक कमा सकते हैं।

2. आय में अस्थिरता और वित्तीय असुरक्षा— कई गिग श्रमिकों को असंगत आय धाराओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वित्तीय नियोजन मुश्किल हो जाता है। सीआईपीडी के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में 51% गिग वर्कर्स

ने वित्तीय असुरक्षा की सूचना दी है।

3. पारंपरिक रोजगार आय के साथ तुलनारु जबकि कुछ गिग श्रमिक अधिक कमाते हैं, अन्य, विशेष रूप से राइड-हेलिंग और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में, अक्सर खर्च और काम किए गए घंटों के लिए लेखांकन करते समय न्यूनतम मजदूरी से कम कमाते हैं।

नौकरी की सुरक्षा और लाभ

पारंपरिक रोजगार सुरक्षा की कमी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है—

1. **पारंपरिक रोजगार सुरक्षा का अभाव**— गिग श्रमिकों के पास आमतौर पर नौकरी की सुरक्षा, भुगतान की गई छुट्टी या अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा नहीं होती है।
2. **नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए लाभों की अनुपस्थिति**— अधिकांश गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति योजना, या भुगतान किए गए समय जैसे लाभ नहीं मिलते हैं, जो औपचारिक रोजगार में मानक हैं। 2023 में एक अध्ययन ने पाया कि केवल 10% गिग वर्कर्स को ही स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। (स्रोत: भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, 2023)
3. **सामाजिक सुरक्षा चिंताएं**— सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता के योगदान की अनुपस्थिति कई गिग श्रमिकों को लंबी अवधि में कमजोर बनाती है।

कौशल विकास और कैरियर प्रगति

गिग वर्क कौशल विकास और कैरियर के विकास के लिए एक अद्वितीय परिदृश्य प्रस्तुत करता है—

1. **विविध कार्य अनुभवों के अवसर**— गिग वर्क व्यक्तियों को विभिन्न परियोजनाओं और उद्योगों में अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देता है, संभावित रूप से उनके कौशल सेट को व्यापक बनाता है।
2. **दीर्घकालिक कैरियर के विकास में चुनौतियां**— गिग वर्क में संरचित कैरियर पथों की कमी पारंपरिक रोजगार की तुलना में दीर्घकालिक कैरियर की प्रगति को कम स्पष्ट कर सकती है।
3. **कौशल अधिग्रहण और अनुकूलनशीलता**— गिग श्रमिकों को अक्सर प्रतिस्पर्धी बने रहने, अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अपने कौशल को लगातार अपडेट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन बाजार की मांगों को बनाए रखने के लिए दबाव भी पैदा करना पड़ता है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएं

गिग वर्क की प्रकृति विशिष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा चुनौतियां पेश कर सकती है—

1. **विशिष्ट गिग क्षेत्रों में व्यावसायिक खतरे**— राइड-हेलिंग और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों को सड़क सुरक्षा और ग्राहकों के साथ संभावित टकराव से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
2. **गिग वर्क के मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव**— गिग वर्क से जुड़ी अनिश्चितता, अलगाव और दबाव तनाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दे सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ ऑक्जूपेशनल एंड एनवायरनमेंटल मेडिसिन द्वारा 2020 के एक अध्ययन में पारंपरिक श्रमिकों की तुलना में गिग वर्कर्स में तनाव का उच्च स्तर पाया गया।
3. **गिग वर्कर्स पर COVID-19**— 19 महामारी का प्रभाव महामारी ने गिग वर्कर्स की भेद्यता को उजागर किया, जिनमें से कई को लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य जोखिमों और आय के अचानक नुकसान का सामना करना पड़ा।

अंत में, जबकि गिग इकॉनमी भारत में कई श्रमिकों के लिए लचीलापन और अवसर प्रदान करती है, यह वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक करियर विकास के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। जैसे-जैसे क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, इन प्रभावों को संबोधित करना गिग श्रमिकों की भलाई और इस आर्थिक मॉडल की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

आर्थिक प्रभाव

भारत में गिग इकॉनमी के तेजी से विकास का देश के आर्थिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यह खंड उन विभिन्न तरीकों की जांच करता है जिनमें गिग अर्थव्यवस्था भारत की व्यापक आर्थिक गतिशीलता को प्रभावित कर रही है।

सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में गिग इकॉनमी का योगदान तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है

1. **वर्तमान और अनुमानित आर्थिक मूल्य**— बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन की

2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिग इकॉनमी में अकेले भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में 90 मिलियन नौकरियों की सेवा करने की क्षमता है, जो काम की मात्रा में \$250 बिलियन से अधिक का लेन-देन करती है और लंबी अवधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धिशील 1.25% का योगदान करती है।

2011-12 से 2017-18 और 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए नीति आयोग ने भी गिग तकवर्कर्स की हिस्सेदारी में वृद्धि को रोजगार लोच में अंतर से भी स्पष्ट किया है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान गिग वर्कर्स के लिए जीडीपी के लिए रोजगार लोच 1 से ऊपर थी और हमेशा समग्र रोजगार लोच से ऊपर थी।

इस अवधि के दौरान रोजगार वृद्धि जीडीपी वृद्धि से लगभग दो गुनी ज्यादा थी। गिग वर्कर्स के लिए उच्च रोजगार लोच आर्थिक विकास की इस प्रकृति को भी स्पष्ट करती है जिसने गिग वर्कर्स के लिए अधिक मांग पैदा की गैर गिग वर्कर्स के तुलना में।

तालिका-1 गिग कार्य रोजगार लोच

वर्ष	गिग कार्य रोजगार वृद्धि	GDP वृद्धि	गिग कार्य लोच	सभी रोजगार लोच
2011-12 to 2017-18	13.020	7.046	1.848	-0.076
2017-18 to 2019-20	13.750	5.280	2.604	1.131

स्रोत- नीति आयोग

2. सेक्टर-वार ब्रेकडाउन- जबकि व्यापक डेटा सीमित है, परिवहन, व्यक्तिगत सेवाओं और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में गिग वर्क से सबसे महत्वपूर्ण योगदान देखा जा रहा है। आईटी और रचनात्मक उद्योग भी महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं।

रोजगार सृजन

गिग इकॉनमी भारत के रोजगार परिदृश्य को नया आकार दे रही है-

1. रोजगार सृजन और श्रम बाजार लचीलापन- गिग अर्थव्यवस्था ने लाखों काम के अवसर पैदा किए हैं, विशेष रूप से उच्च बेरोजगारी दर वाले देश में फायदेमंद है। इसने श्रम बाजार में अभूतपूर्व लचीलापन पेश किया है। नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार गिग वर्कर्स की संख्या 2011-12 में 24.5 जबकि 2019-20 में 67 लाख हो गई, साथ ही जिन लोगों ने वर्ष की छोटी अवधि के लिए (सामान्य सहायक स्थिति) इस प्रकार का काम किया है उनकी संख्या 2011-12 से 2019-20 की अवधि के दौरान 0.7 से बढ़कर 1.1 लाख हो गई।

यूपीएस वर्कर्स के मामले में यह 1.37: था और सहायक स्थिति वाले सहायक कर्मचारी का केवल 0.49% था। हालांकि कुल श्रमिकों में गीत वर्कों की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हो रही है जो 2011-12 में 0.54% से बढ़कर 2019-20 में 1.33% हो गई है।

तालिका-2 कुल कार्यबल में गिग श्रमिकों के हिस्सेदारी (2011-12 से 2019-20 तक)

Year	गिग वर्कर्स की संख्या लाखों में (UPS)	कुल कार्यबल के हिस्से के रूप में गिग वर्कर्स का हिस्सा (UPS)	गिग वर्कर्स की संख्या लाखों में (USS)	कुल कार्यबल के हिस्से के रूप में गिग वर्कर्स का हिस्सा (USS)	गिग वर्कर्स की संख्या लाखों में (UPSS)	कुल कार्यबल के हिस्से के रूप में गिग वर्कर्स का हिस्सा (UPSS)
2011-12	24.5	0.57	0.7	0.18	25.2	0.54
2017-18	52.1	1.18	0.5	0.40	52.6	1.16
2018-19	53.4	1.18	0.5	0.28	53.9	1.15
2019-20	67.0	1.37	1.1	0.49	68.0	1.33

स्रोत- नीति आयोग

2. बेरोजगारी दर पर प्रभाव- जबकि आधिकारिक बेरोजगारी के आंकड़े पूरी तरह से गिग वर्क पर कब्जा नहीं करते हैं, वास्तविक सबूत बताते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था ने कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित करने में मदद की है, खासकर शहरी क्षेत्रों में।

3. अनौपचारिक कार्य का औपचारिककरण- कुछ मामलों में, गिग प्लेटफार्मों ने पहले अनौपचारिक कार्य व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देने में मदद की है, संभावित रूप से इन आर्थिक गतिविधियों की बेहतर ट्रैकिंग और विनियमन के लिए अग्रणी बनाने में की है। तालिका-3 में यह देखा जा सकता है कि गिग वर्कर्स की हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र में केंद्रित है, 2019-20 में कुल गिग वर्कर्स का लगभग 62.4 % असंगठित क्षेत्र में है। हालांकि संगठित

क्षेत्र में गिग श्रमिकों के हिस्सेदारी 2011-12 में 26 थी जो 2019-20 में बढ़कर 37.6% हो गई। परंतु अनौपचारिक श्रमिकों की हिस्सेदारी इस अवधि में कमोबेश समान रही है या मामूली रूप से बढ़ी है।

तालिका-3: गिग श्रमिकों की हिस्सेदारी संगठित और असंगठित क्षेत्र व औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में

वर्ष	% संगठित क्षेत्र में	% असंगठित क्षेत्र में	कुल	% में औपचारिक क्षेत्र	% अनौपचारिक क्षेत्र में	कुल
2011-12	25.9	74.1	100	16.3	83.7	100
2017-18	30.6	69.4	100	18.2	81.8	100
2018-19	35.7	64.3	100	18.6	81.4	100
2019-20	37.6	62.4	100	17.5	82.5	100

स्रोत- नीति आयोग

पारंपरिक उद्योगों पर प्रभाव

गिग अर्थव्यवस्था का उदय कई पारंपरिक क्षेत्रों को बाधित कर रहा है-

- परिवहन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में व्यवधान-** राइड-हेलिंग और होम-शेयरिंग प्लेटफार्मों ने पारंपरिक टैक्सी सेवाओं और होटल उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, जिससे इन क्षेत्रों में नवाचार और चुनौतियां दोनों पैदा हुई हैं।
- व्यापार मॉडल और प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन-** कई पारंपरिक व्यवसाय गिग मॉडल को अपना रहे हैं, या तो गिग श्रमिकों को अपने संचालन में शामिल करके या गिग इकोनॉमी स्टार्टअप के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्लेटफॉर्म-आधारित सेवाओं को विकसित करके।

उत्पादकता और नवाचार

गिग अर्थव्यवस्था इस बात में बदलाव ला रही है कि काम कैसे किया जाता है और व्यवसाय कैसे संचालित होते हैं।

- लचीली कार्य व्यवस्था के माध्यम से दक्षता लाभ-** मांग के आधार पर कार्यबल को तेजी से ऊपर या नीचे करने की क्षमता व्यवसायों के लिए दक्षता में वृद्धि कर सकती है।
- उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना-** गिग इकोनॉमी ने उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कई प्रकार के व्यवसायों के लिए प्रवेश के लिए बाधाओं को कम किया है।

आय वितरण और असमानता

आय वितरण पर गिग अर्थव्यवस्था का प्रभाव जटिल और बहुआयामी है-

- आय धुवीकरण की संभावना-** जबकि कुछ उच्च-कुशल गिग श्रमिक पर्याप्त आय अर्जित करते हैं, कई कम-कुशल गिग श्रमिक कम और अस्थिर आय के साथ संघर्ष करते हैं, संभावित रूप से आय असमानता को बढ़ाते हैं।
- आर्थिक गतिशीलता पर प्रभाव-** कुछ के लिए, गिग वर्क उच्च आय और आर्थिक गतिशीलता का मार्ग प्रदान करता है। दूसरों के लिए, यह अनिश्चित रोजगार के एक रूप का प्रतिनिधित्व कर सकता है जो दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता में बाधा डालता है।

कर निहितार्थ

गिग अर्थव्यवस्था कर अधिकारियों के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है।

- गिग वर्कर्स से टैक्स कलेक्शन में चुनौतियां-** गिग वर्क की विकेंद्रीकृत प्रकृति और गिग वर्कर्स की अक्सर अनौपचारिक स्थिति टैक्स अधिकारियों के लिए टैक्स को प्रभावी ढंग से ट्रैक करना और इकट्ठा करना मुश्किल बना देती है।
- टैक्स रेवेन्यू का संभावित नुकसान-** अगर गिग इकोनॉमी ऐक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रिपोर्ट नहीं किया जाता है या कम टैक्स किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार के लिए टैक्स रेवेन्यू का काफी नुकसान हो सकता है।

अंत में, गिग इकोनॉमी का भारत के आर्थिक परिदृश्य पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है। जबकि यह जीडीपी वृद्धि, रोजगार सृजन और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है, यह श्रमिक संरक्षण, आय असमानता और कर संग्रह के मामले में भी चुनौतियां प्रस्तुत करता है।

नियामक पर्यावरण

भारत में गिग इकॉनमी के तेजी से विकास ने नियामक ढाँचे के विकास को पीछे छोड़ दिया है, जिससे नीति निर्माताओं, व्यवसायों और श्रमिकों के लिए समान रूप से एक जटिल परिदृश्य बन गया है। यह खंड भारत में गिग वर्क के आसपास के वर्तमान नियामक वातावरण और इस विकसित क्षेत्र को नियंत्रित करने में चुनौतियों की जांच करता है।

वर्तमान श्रम कानून और गिग कार्य के लिए उनकी प्रयोज्यता

- मौजूदा श्रम कानूनों में अंतरालरू भारत के अधिकांश श्रम कानून पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे, जिससे गिग वर्क पर लागू होने पर महत्वपूर्ण अंतराल रह जाते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 जैसे प्रमुख कानून स्पष्ट रूप से गिग श्रमिकों को कवर नहीं करते हैं।

- गिग श्रमिकों को वर्गीकृत करने में चुनौतियाँ— गिग श्रमिकों की अस्पष्ट स्थिति है, वह न तो पूरी तरह से कर्मचारी और न ही पारंपरिक अर्थों में स्वतंत्र ठेकेदार है। यह मौजूदा श्रम सुरक्षा को लागू करने में कठिनाइयाँ पैदा करती हैं। यह वर्गीकरण चुनौती गिग अर्थव्यवस्था के आसपास कई नियामक बहसों के केंद्र में है।

हाल की नीतिगत पहल

1. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020**— यह ऐतिहासिक कानून श्रम कानून में गिग वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता देने का भारत का पहला प्रयास है। इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं—

- गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की परिभाषा
- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने का प्रावधान
- एग्रीगेटर्स को अपने वार्षिक कारोबार का 1–2% इस फंड में योगदान करने की आवश्यकता

हालाँकि, इस कोड के कार्यान्वयन में देरी हुई है, परंतु कई विवरणों को स्पष्ट किया जाना बाकी है।

2. **राज्य-स्तरीय नियम**— कुछ राज्यों ने गिग अर्थव्यवस्था के पहलुओं को विनियमित करने के लिए पहल की है। उदाहरण के लिए—

- कैब एग्रीगेटर्स पर कर्नाटक के नियम, ड्राइवरों के लिए न्यूनतम किराया और अधिकतम काम के घंटे निर्धारित करना
- खाद्य वितरण प्लेटफॉर्मों के लिए महाराष्ट्र के दिशानिर्देश, सर्ज प्राइसिंग और श्रमिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए।

विनियमन में चुनौतियाँ

1. **श्रमिक सुरक्षा और व्यावसायिक लचीलेपन को संतुलित करना**— नियामकों को गिग अर्थव्यवस्था की विशेषता वाले लचीलेपन और नवाचार को दबाए बिना गिग श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
2. **प्रवर्तन मुद्दे**— गिग वर्क की विकेंद्रीकृत प्रकृति और व्यवसाय मॉडल का तेजी से विकास नियमों के प्रवर्तन को चुनौतीपूर्ण बनाता है। कई गिग वर्कर्स ग्रे एरिया में काम करते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए अनुपालन की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

1. अन्य देशों में नियामक दृष्टिकोण—

- **यूनाइटेड किंगडम**— सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उबर ड्राइवरों को श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जो न्यूनतम वेतन और अवकाश वेतन के हकदार हैं।
- **कैलिफोर्निया, यूएसए**— एबी 5 कानून, जिसे बाद में प्रस्ताव 22 द्वारा संशोधित किया गया, ने कई गिग श्रमिकों को कर्मचारियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का प्रयास किया।
- **यूरोपीय संघ**— प्रस्तावित निर्देशों का उद्देश्य मंच श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना है।

2. **भारत के लिए सबक**— हालाँकि ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, भारत के अद्वितीय आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में अनुरूप समाधान की आवश्यकता है। भारत की गिग अर्थव्यवस्था का विशाल पैमाना और इसके कार्यबल की विविधता अलग-अलग नियामक चुनौतियाँ पेश करती है।

भविष्य का नियामक दृष्टिकोण

1. नए कानून के लिए संभावित क्षेत्र

- विभिन्न प्रकार के गिग वर्क की स्पष्ट परिभाषाएँ
- समय-आधारित गिग कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी
- डिजीलरी और राइड-हेलिंग जैसे क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा मानक
- गिग श्रमिकों के लिए डेटा संरक्षण नियम

2. विनियमन पर हितधारक दृष्टिकोण—

- गिग वर्कर्स और यूनियन आम तौर पर मजबूत सुरक्षा और लाभों की वकालत करते हैं
- प्लेटफॉर्म कंपनियाँ अक्सर लचीलापन बनाए रखने और अति-विनियमन से बचने के लिए तर्क देती हैं
- सरकारी निकाय आर्थिक विकास और नवाचार के साथ श्रमिक कल्याण को संतुलित करने की मांग कर रहे हैं

निष्कर्ष—भारत में गिग इकॉनमी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, जो आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण विकास और परिवर्तन के लिए तैयार है। इस शोधपत्र ने भारत की गिग अर्थव्यवस्था की बहुमुखी प्रकृति का पता लगाया है, इसकी वर्तमान स्थिति, प्रमुख चालकों और बाधाओं, क्षेत्रीय प्रभावों, नीतिगत निहितार्थों और संभावित भविष्य के परिदृश्यों की जांच की है। इस अध्ययन में कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि उभरती हैं, जैसा कि भारत की युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी वैश्विक गिग अर्थव्यवस्था परिदृश्य में एक अनूठा लाभ प्रदान करती है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और विस्तारित गिग सेक्टर के बीच तालमेल युवा बेरोजगारी को संबोधित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है। हालांकि, इस क्षमता का दोहन करने के लिए सावधानीपूर्वक नीति नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता होगी।

ब्लॉकचेन और IoT जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ बढ़ी हुई दक्षता और नए काम के अवसरों का वादा करती हैं, वे नौकरी विस्थापन और निरंतर अपस्किलिंग की आवश्यकता के बारे में भी चिंता जताते हैं। गिग अर्थव्यवस्था का प्रभाव सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है, कुछ में आमूल-चूल व्यवधान का अनुभव होता है और अन्य में अधिक क्रमिक परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे-जैसे गिग अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यह कई उद्योगों में पारंपरिक और गिग कार्य के बीच की रेखाओं को धुंधला करने की संभावना है, जिससे व्यवसायों और श्रमिकों दोनों से अनुकूली रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

गिग अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास ने नियामक ढांचे को पीछे छोड़ दिया है, जिससे एक जटिल नीति परिदृश्य बन गया है। कार्यकर्ता सुरक्षा के साथ नवाचार को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। श्रमिक वर्गीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाली व्यापक, अनुकूली नीतियों का विकास भारत में गिग वर्क के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा। जबकि गिग इकॉनमी आय सृजन के लिए लचीलापन और अवसर प्रदान करती है, यह आय स्थिरता, करियर की प्रगति और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों को भी प्रस्तुत करती है। इन मुद्दों का समाधान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि गिग इकॉनमी की वृद्धि भारत के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास में सकारात्मक योगदान दे।

हमारे परिदृश्य विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की गिग अर्थव्यवस्था का भविष्य विभिन्न तरीकों से सामने आ सकता है, जिसमें षगिग क्रांति से लेकर श्रम बाजार को षगिग डिवाइड में बदल दिया जाता है जो असमानताओं को बढ़ाता है। अंत में, भारत में गिग अर्थव्यवस्था का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि विभिन्न हितधारकों के सामूहिक कार्यों द्वारा आकार दिया जाएगा। चुनौतियों का अनुमान लगाकर, अवसरों का लाभ उठाकर, और एक समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, भारत एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकता है जहां गिग इकॉनमी व्यापक समृद्धि और आर्थिक लचीलापन में योगदान देती है।

अंत में, भारत में गिग अर्थव्यवस्था के लिए नियामक वातावरण प्रवाह की स्थिति में है। जबकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जैसी हालिया पहलें, महत्वपूर्ण कदमों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इस गतिशील क्षेत्र को प्रभावी ढंग से विनियमित करने में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जैसे-जैसे गिग इकॉनमी विकसित हो रही है, यह संभावना है कि भारत के नियामक ढांचे को श्रमिकों, व्यवसायों और व्यापक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को संतुलित करते हुए लगातार अनुकूलन करने की आवश्यकता होगी।

Author's Declaration:

The views and contents expressed in this research article are solely those of the author(s). The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible for any errors, ethical misconduct, copyright infringement, defamation, or any legal consequences arising from the content. All legal and moral responsibilities lie solely with the author(s).

संदर्भ

1. अग्रवाल, ए., गैन्स, जे., और गोल्डफार्ब, ए. (2020). 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अर्थव्यवस्थाएँ एक एजेंडा'. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस.
2. एसोचौम. (2020). 'गिग इकॉनमीरू काम के भविष्य को आकार देना'. एसोसिएटेड चॉबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया.
3. बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और माइकल एवं सूसन डेल फाउंडेशन. (2021). 'भारत में गिग इकॉनमी की क्षमता को उजागर करना'. बीसीजी रिपोर्ट
4. फोरसाइट फैक्ट्री. (2021). 'गिग इकॉनमी का भविष्य 2030 के लिए वैश्विक परिदृश्य'. फोरसाइट फैक्ट्री रिपोर्ट.
5. इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन. (2024). 'भारत में लचीली स्टाफिंग पर वार्षिक रिपोर्ट'. आईएसएफ रिपोर्ट.
6. मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट. (2016). 'स्वतंत्र कार्यरत पसंद, आवश्यकता और गिग इकॉनमी'. मैकिन्से एंड कंपनी.
7. नीति आयोग. (2022). 'भारत की बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म इकॉनमी'. नीति आयोग रिपोर्ट.
8. विश्व बैंक. (2023). 'युवाओं के लिए डिजिटल नौकरियाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था में युवा महिलाएं'. विश्व बैंक समूह. कार्यपत्र (Working Papers)
9. अग्रवाल, ए., गैन्स, जे., और गोल्डफार्ब, ए. (2021). 'एआई अपनाता और सिस्टम-व्यापी परिवर्तन'. वर्किंग पेपर 28811 नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक
10. डी स्टेफानो, वी. (2015). 'प्लेटफॉर्म-इकॉनमी का उदय और ऑनलाइन-डिमांड वर्क, क्राउडवर्क और गिग-इकॉनमी में श्रम सुरक्षा'. 'कम्पैरेटिव लेबर लॉ एंड पॉलिसी जर्नल', 37, 471.
11. फ्रीडमैन, जी. (2014). 'नियोक्ताओं के बिना श्रमिकों के शैडो कॉर्पोरेशन और गिग इकॉनमी का उदय'. 'रिव्यू ऑफ केनेसियन इकोनॉमिक्स', 2(2), 171-188.
12. हीक्स, आर., ग्राहम, एम., मुंगाई, पी., वान बेले, जे. पी., और वुडकोक, जे. (2021). 'उचित कार्य मानकों के विरुद्ध गिग वर्क का व्यवस्थित मूल्यांकन फेयरवर्क फ्रेमवर्क का विकास और अनुप्रयोग'. 'द इंफॉर्मेशन सोसाइटी', 37(5), 267-286.
13. काश्यप, आर., और भाटिया, ए. (2018). 'टैक्सी ड्राइवर और टैक्सीदार: दिल्ली में उबर और ओला का केस स्टडी'. 'जर्नल ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज', 34(2), 169-194.
14. कास्सी, ओ., और लेहडोनविर्ता, वी. (2018). 'ऑनलाइन लेबर इंटेक्सरू नीति और अनुसंधान के लिए ऑनलाइन गिग इकॉनमी को मापना'. 'टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग एंड सोशल चेंज', 137, 241-248.
15. रामचंद्रन, ए., और रमन, ए. (2022). 'भारतीय गिग इकॉनमी: आगे का रास्ता'. 'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली', 57(22), 20-23.
16. सूरी, ए. (2018). 'क्या ओला और उबर ड्राइवर उद्यमी हैं या शोषित श्रमिक?'. 'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली', 53(24), 1-7.
17. वल्लास, एस., और शोर, जे. बी. (2020). 'प्लेटफॉर्म क्या करते हैं? गिग इकॉनमी को समझना'. 'एनुअल रिव्यू ऑफ सोशियोलॉजी', 46, 273-294.
18. वुड, ए. जे., ग्राहम, एम., लेहडोनविर्ता, वी., और हजोर्थ, आई. (2019). 'अच्छी गिग, बुरी गिगरू वैश्विक गिग इकॉनमी में स्वायत्तता और एल्गोरिदमिक नियंत्रण'. 'वर्क, एम्प्लॉयमेंट एंड सोसाइटी', 33(1), 56-75.
19. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन. (2021). 'विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण 2021रू काम की दुनिया को बदलने में डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म की भूमिका'.
20. कासलीवाल, आर. (2020). 'लिंग और गिग इकॉनमी: महिला श्रमिकों के लिए गिग प्लेटफॉर्म का गुणात्मक अध्ययन'. ओआरएफ इश्यू ब्रीफ नं. 359, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन
21. कोरेक, एस. (2018). 'भारतीय गिग-इकॉनमीरू कोविड-19 के प्रभाव की खोज'. ओआरएफ इश्यू ब्रीफ नं. 359, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन.

Cite this Article-

'डॉ० विजया कुमारी' 'डिजिटल बाजार में गिग इकोनमी का प्रभावः भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में', *Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ)*, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:08, August 2025.

Journal URL- <https://www.researchvidyapith.com/>

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i80007

Published Date- 09 August 2025